



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2018/चैत्र 13, 1940

No. 139]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018/ CHAITRA 13, 1940

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसचना

मुंबई, 21 मार्च, 2018

**सं. टीएएमपी/30/2014-पीपीटी.**— महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) पर निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की हार्बर चल क्रेनों (एचएमसी) के प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### मामला संख्या टीएएमपी/30/2014-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्याय

---

आवेदक

### गणपूर्ति

- (i). श्री टीएस. बालसुब्रमनियन (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(मार्च, 2018 के 19 वें दिन पारित)

मामला निजी प्रचालकों द्वारा परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) पर 100 टन क्षमता की हार्बर चल क्रेन (एचएमसी) के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. पीपीटी द्वारा दायर एक प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने 28 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएमपी/30/2014-पीपीटी के द्वारा बिना किसी विशिष्ट सेवा प्रदाता के हवाले से, कॉमन प्रयोजन के लिए, पीपीटी पर एचएमसी के उपयोग का अधिकतम प्रशुल्क निर्धारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् प्रभावी होना था यानी 4 फरवरी, 2015 से और यह तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है यानी 3 फरवरी, 2018 तक।

3. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने अपने 13/15 फरवरी, 2018 के पत्र संख्या ईएम/डब्ल्यूएस/टेक/04/(पीटी-4)/365 के द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:

- (i). वर्तमान में पीपीटी ने विभिन्न क्षमता वाले यानी 80 टन और 100 टन, के 8 एचएमसी प्रचालकों को लाइसेंस मंजूर किया है। 8 में से 100 टन क्षमता की 7 एचएमसी और 80 टन क्षमता की एक एचएमसी है।
- (ii). निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित और पीपीटी पर प्रचालित 100 टन क्षमता की प्रशुल्क की वैधता जिसे प्राधिकरण द्वारा 5 जनवरी, 2015 के राजपत्र संख्या 7 में अधिसूचित किया गया है, समाप्त हो गई है।
- (iii). 100 टन क्षमता की एचएमसी के प्रशुल्क के संशोधन का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा। इसी बीच, 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का विस्तार 3 अगस्त, 2018 तक या 100 टन क्षमता की एचएमसी के लिए नियत किये जाने वाले नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, किये जाने का अनुरोध किया जाता है।
- (iv). इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने अपने 24 जुलाई, 2015 के आदेश संख्या टीएमपी/54/2007-पीपीटी के द्वारा पीपीटी पर सीआईडब्ल्यू द्वारा स्थापित 80 टन क्षमता का प्रशुल्क भी नियत किया था। सीआईडब्ल्यू द्वारा स्थापित 80 टन क्षमता की लाइसेंस अवधि 25 फरवरी, 2019 को समाप्त होगी। और कथित संविदा को अधिकतम राजस्व हिस्सेदारी के अनुसार अंतिम रूप दिया गया था अर्थात् 32.60 रु. प्रति एमटी। अतः इन परिस्थितियों में, 80 टन क्षमता की एचएमसी की वैधता का विस्तार 25 फरवरी, 2019 तक करने का अनुरोध किया जाता है अर्थात् लाइसेंस करार की समाप्ति की तारीख तक, क्योंकि, 80 टन एचएमसी का प्रशुल्क संशोधन 1 वर्ष की अवधि के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता।

4.1. पीपीटी द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में, जैसा ऊपर पैरा संख्या 3 (i), (ii) और (iii) में बताया गया है, यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि पीपीटी पर निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता पहले ही 3 फरवरी, 2018 को समाप्त हो गई है। पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के संसाधन की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को देखते हुए, वर्तमान दरमानों की वैधता को 3 फरवरी, 2018 से आगे बढ़ाना उपयुक्त महसूस किया जाता है। तथापि, पीपीटी ने उस समय का संकेत नहीं दिया है कि वह कब तक अपना प्रस्ताव दायर करेगा।

4.2. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता को 3 अगस्त, 2018 तक या 100 टन क्षमता की एचएमसी के लिए नियत नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक जो भी पहले हो, पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना प्रस्ताव 30 अप्रैल, 2018 तक प्रस्तुत करे दे।

5. इसके अतिरिक्त, पीपीटी द्वारा किये गए निवेदन के संबंध में, जैसा ऊपर पैरा 3(iv) में बताया गया है, यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस प्राधिकरण का 2 जुलाई, 2015 को आदेश संख्या टीपीएमपी/54/2007-पीपीटी माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय, द्वारा किये गए निदेशों के अनुसरण में पारित किया गया था और प्रशुल्क जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. (जेएसपीएल) द्वारा स्थापित 140 टन एचएमसी और चैन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. (सीआरईडब्ल्यू) द्वारा स्थापित 100 टन एचएमसी के लिए 23 जनवरी, 2010 से 22 जनवरी, 2013 की अवधि के लिए नियत किया गया था (जैसा 30 दिसम्बर, 2009 के आरम्भिक आदेश संख्या टीएमपी/54/2007-पीपीटी द्वारा कवर है)। जब सीआरईडब्ल्यू द्वारा स्थापित 80 टन एचएमसी के लिए कोई प्रशुल्क नियत ही नहीं किया गया, तो उसका एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसे पीपीटी ने अनुरोध किया है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 13 / 18]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**Mumbai, the 21<sup>st</sup> March, 2018

**No. TAMP/30/2014-PPT.**— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for 100 Tonne capacity Harbour Mobile Crane (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust (PPT), as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No. TAMP/30/2014-PPT****Paradip Port Trust**

---

**Applicant****QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**O R D E R**(Passed on this 19<sup>th</sup> day of March 2018)

This case deals with the extension of the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity Harbour Mobile Crane (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust (PPT).

2. Based on a proposal filed by the PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/30/2014-PPT dated 28 November 2014 has fixed ceiling tariff for the use of HMC at the PPT, for common application, without reference to any particular service provider. This Order was notified in the Gazette of India on 5 January 2015 and had come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order i.e. 4 February 2015 and is valid for a period of three years i.e. upto 3 February 2018.

3. In this backdrop, the PPT vide its letter no. EM/WS/TECH/04/(PT-I)/365 dated 13/15 February 2018 has submitted as follows:

- (i). At present PPT has granted License to 8 nos. of HMC Operators having different capacities i.e. 80 tonnes and 100 tonnes. Out of 8 nos., 7 nos. of HMCs are of 100 tonne capacity and 1 no. of HMC is of 80 tonne capacity.
- (ii). The validity of the tariff for 100 tonne capacity HMC installed by private operators and operating at PPT, which has been fixed by TAMP vide Gazette notification no. 07 dated 05 January 2015, has expired.
- (iii). Preparation of fresh proposal for revision of tariff of 100 tonne capacity HMC is under process and will be finalised soon. In the meanwhile, it is requested to extend the validity of the existing tariff of 100 tonne capacity HMC upto 03 August 2018 or till effective date of implementation of new tariff fixed for 100 tonne capacity HMC, whichever is earlier.
- (iv). Further, TAMP has also fixed tariff for 80 tonne HMC installed by CREW at PPT vide Order no. TAMP/54/2007-PPT dated 24 July 2015. The License period of 80 tonne HMC installed by CREW will expire on 25 February 2019 and the said contract was finalised as per the highest revenue sharing i.e. ₹ 32.60 per MT. Hence, under this circumstances, it is requested to extend the validity of the 80 tonne capacity HMC upto 25 February 2019 i.e. upto the expiry date of Licence Agreement, since revision of tariff for 80 tonne HMC for a period of 1 year may not be feasible.

4.1. With regard to the submission made by PPT, as brought out at para no. 3 (i), (ii) and (iii) above, it is relevant here to mention that the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity HMC installed by private operators at PPT has already expired on 3 February 2018. Considering the time required for processing the proposal to be filed by the PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR beyond 3 February 2018. The PPT has, however, not indicated the time by which it would submit its proposal.

4.2. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity HMC installed by private operators at PPT upto 3 August 2018 or till the effective date of implementation of new tariff to be fixed for 100 tonne capacity HMC based on the proposal to be filed by PPT, whichever is earlier. The PPT is advised to submit its proposal by 30 April 2018.

5. Further, with regard to the submission made by PPT as brought out at para no. 3(iv) above, it is relevant here to mention that vide the Order no. TAMP/54/2007-PPT dated 2 July 2015 passed by this Authority, in compliance of the directions of the Hon'ble High Court of Orissa, tariff was fixed for the 140 tonne HMC installed by Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) and 100 tonne HMC installed by Chennai Radha Engineering Works Pvt. Ltd. (CREW), for the period from 23 January 2010 to 22 January 2013 (as covered by the initial Order no. TAMP/54/2007-PPT dated 30 December 2009). When no tariff has been fixed for an 80 tonne HMC installed by CREW, the question of extending its validity for a period of 1 year as requested by PPT, does not arise.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./13/18]